[Shri Chintamani Pangirahi]

sary to do that to help the poor people in the country.

Let me quote the words of the Prime Minister. I quote:

> "Who derives his entire income from wealth, the combined effort of income and wealth taxation, as now proposed, will impose an effective ceiling on income after tax when such income reaches approximately Rs. 25,000 per annum."

For the first time, the Wealth Tax rates on urban land and buildings has been raised. The Wealth Tax rates have been raised from the existing levels of 0.5 per cent. The exemption limit for Gift Tax has been lowered from 10,000 to Rs. 5,000. The Company entertainment expenses have been disallowed for tax exemption. The flat rate of 65% on the income of discretionary trusts is also a well-designed measure to check tax evasion. These trusts were being mismanaged like anything. They were extending their empire. This is the first time that we are attacking these trusts. Therefore, if all this does not distinguish the Budget of 1970-71 from the budget of 1969-70, then what makes the difference? I hope, Sir, the trend and direction shown in the budget will pave the way for better understanding between the forces of progress, the forces of democracy and the forces of socialism and they shall try to adjust with each other and will provide such a kind of solid rocklike understanding that the forces of reaction will be defeated in all their conspiracies. A beginning has been made in the right direction and I am quite sure, that if the corporate sector had been left untouched to-day, it is like a goat being prepared for the next year's sacrifice.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का रंज नहीं है कि. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue tomorrow.

DISCUSSION RE: WESTERN KOSI CANAL, ASHOKA AND THAKUR PAPER MILLS, AND MITHILA UNIVERSITY AND MITHILA BROADCASTING STATION

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then we take up the half-an-hour discussion. Mr. Bhogendra Jha, you have raised four or five matters for this half-an-hour discussion. I stand corrected. This is not an half-an-hour discussion, but it is a discussion under Rule 193. But only half an hour has been allotted for it. After you speak, we cannot allow any other members and I will call upon the Ministers to reply.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Every Party should be given a chance.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat. I am listening to other members. You are not the only member here. I cannot hear anybody if everybody talks. Please sit down. I am running this House. I know what I am doing let me here.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, हर एक पार्टी को कुछ समय दिया जाये ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कर दिया जाये कि क्या अन्य पार्टियों के सदस्यों को समय मिलेगा या नहीं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am entirely in your hands. If others speak, you cannot conclude this discussion in half an hour. Therefore, you have to decide one way or the other. It is not possible. Kindly hold on. About four or five Ministers are involved in this discussion. If you want them to say something in reply to all the points raised, then you must forgo the rignt to speak.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): May we know whether there is such a wise Minister who can reply on behalf of all the Ministers?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no one Minister who can speak on behalf of all the other Ministers. Perhaps the only person who can do that is the Prime Minister. It is not possible for her to do that. Let us not waste time on this. If you all agree, I will call Mr. Jha to make his submission and those Ministers who are here will reply.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): Sir, this is a discussion under Rule 193.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But only half an hour has been allotted for this.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल उठाने जा रहा हूं, वह उस इलाके से संबंध रखता है,जो हमारे देश का सब से अधिक आबादी वाला जिला है । और दूसरा कोई जिला अपने देश में नहीं है जिस की आबादी 55 लाख होगी । तो 55 लाख की आबादी वाला वह जिला जो उत्तर बिहार के पिछड़े इलाके के मध्य में पड़ता है उस के उद्योग-धन्धे, उस की कृषि, उस की तालीम, इन सब के पिछड़ाव को कायम रखा गया है और जो मसौदा तैयार हो रहा है चौथी पंच साला योजना के लिए उस में अगले पांच साल के लिए उस के पिछड़ेपन की गारंटी की गई है जिस के खिलाफ वहां असंतोष फूट पड़ा है । मैं आप के जरिए इस सदन को और सरकार को जताना चाहता हूं कि अगर इन के दिमाग में यह बात नहीं है तो यह बात समझलें, पिछले कई महीने में, पहली मई को पूरे दरभंगा शहर के बाजार बन्द रहे थे, जिला बन्द मनाया गया था । अभी 13 फरवरी को सभी कालेज स्कूल वगैरह बन्द रहे, छात्रों की, शिक्षकों की हड़ताल रही और 20 से 28 फरवरी तक 11 हजार लोगों ने सत्याग्रह किया जिस में तीन हजार गिरफ्तार हुए और सौ से ऊपर लाठी वगैरह से घायल हुए हैं । एक ही कुसूर उन का, वहां के लोगों का है कि अभी तक उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है और तोड़फोड़ का रास्ता नहीं अपनाया है । केवल अपने बदन पर एक तरफा चोट बर्दाश्त की है । और यही कारण है कि इस भारत सरकार का दिमाग अभी तक साफ नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है । अगर मैं यह समझता कि कोई खास मजबूरी है तो मैं खुद ही इस में मदद करने की हालत में अपने को पाता । लेकिन मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखता हूं ।

पश्चिमी कोसी नहर की योजना है । वह इलाका नेपाल के नीचे पड़ता है । जितनी हिमालय की नदियां उस इलाके से हो कर बहती हैं वह अपने साथ सिल्ट भी लाती है, थोड़ी वर्षा के बाद बाढ़ और कुछ भी वर्षा नहीं होने पर सूखा, अभी वहां अकाल की स्थिति है और बिहार सरकार ने भी कुछ इस सिलसिले में कार्य शुरू कर दिया है, इसी सब को ध्यान में रखते हुए कोसी नहर योजना बनाई गई थी जिस योजना से भारत को फायदा है, और नेपाल को भी फायदा है । अब बार बार सिंचाई मंत्रालय से कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार उस के लिए तैयार नहीं हो रही है । मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि इस के जरिए सिंचाई विभाग के मंत्री, सिंचाई विभाग के अभियंता वगैरह हम को अपने पड़ौसी देश के साथ क्यों कि नेपाल सिर्फ हमारा पड़ौसी देश ही नहीं है, सिर्फ मित्र नहीं है, हमारा एक सहोदर देश है, उस के साथ यह रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नाकामी का सेहरा उन के सिर पर थोपना चाहते हैं । नेपाल की सरकार चाहती है कि नहर को थोड़ा और ऊपर ले जाना जिस से नेपाल को भी फायदा है और भारत को भी फायदा है । भारत की दो लाख एकड़ जमीन ज्यादा पटेगी और नेपाल की भी लगभग डेढ़ लाख एकड़ ज्यादा जमीन पटेगी । हमें फायदा है उस से । लेकिन सिंचाई विभाग के कुछ अभियन्ता उस के लिए तैयार नहीं हैं । मेरी अपनी बातचीत चीफ इंजिनियर से हुई थी । उन्होंने कहा कि हमारा खर्चा बढ़ जायगा । हमने कहा कि खर्चा बढ़ेगा तो उस से नेपाल की जो ज्यादा जमीन पटेगी वह अलग छोड़ दीजिए, हमारी भी इतनी जमीन ज्यादा पटेगी । उन्होंने कहा कि यह आप सोचिएगा राजनैतिक दृष्टि से कि फायदा होगा नेपाल के हिसाब से, हम उस दृष्टि से नहीं सोच सकते हैं । दूसरे, कमला का तटबन्ध हम ने बनाया है नेपाल की सरहद् तक

[श्री भोगेन्द्र झा]

जयनगर तक चला गया है। यह शर्त थी कि उस को सीसापानी तक, हिमालय तक ले जाएंगें। उस शर्त को पूरा नहीं किया और जो बिहार सरकार से खत मिला है उस के मुताबिक वह केंद्रिय वाटर ऐंड पावर कमिश्नर के पास पड़ा हुआ है। ऊपर तक वह तटबन्ध हम नहीं ले जा सके। हम लोग अपने यहां पानी का तटबंधों में फेर लेते हैं तो पूरा पानी नेपाल में बह जाता है और सैकड़ों गांव उन के डूब जाते हैं। फिर वह पानी हमारे यहां आ जाता है। भारत सरकार पिछले 6 सालों से उस को टाले हुए हैं। जब हम लोग नेपाल गए थे, हम ने देखा वहां के मंत्री हैं, वहां की सरकार उद्यत है, वहां के नेपाल के राजा भी उद्यत हैं और सभी चाहते हैं कि यह कार्य हो। लेकिन उस सम्बन्ध को पूरा नहीं किया और इसलिए पचिश्मी कोसी की नहर के नाम पर उन को हिचक है कि होगी या नहीं। मैं आप के जरिए सदन से कहना चाहता हूं कि हर बार कहा जा रहा है कि बड़े ऊंचे स्तर पर बात हो रही है, तो मेरा आग्रह है कि ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ तो जरा सोचे नीचे स्तर पर कोशिश करें, कुछ मंत्री चले, कुछ उस इलाके के सदस्य चलें और हम लोगों का विश्वास है कि उस में उन का फायदा है, हमारा फायदा है, वह काम हो जायगा। वहां के लोग, वहां के मंत्री, वहां के अधिकारी उत्सुक हैं और निश्चित रूप से यह काम हो जायगा। इस में मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग वहां जाते हैं जो नेपाल से हमारे संबंध को समझ नहीं सकते।। ऐसी स्थिति में फिर भी जो मसौदा तैयार हुआ था, पिछले साल सब से जो आखिरी चिट्ठी मुझे मिली है वह यह है :

> In the draft forth five-year plan for 1969-74 prepared in August 1968 a provision of Rs. 500 lakhs has been made but since no final approval has come this provision was reduced to Rs. 50 lakhs only. This total provision of Rs. 50 lakhs can be [augmented if the Planning Commission agrees to provide . more funds.

तो 20 करोड़ की यह योजना है। 5 करोड़ पहले मसौदे में 68 में दिया गया था और अब जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें उस को घटा कर 50 लाख कर दिया गया है अगले पांच सालों के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर इस सरकार के निकम्मेपन के चलते संभव ही नहीं हो कि नेपाल सरकार उस की स्वीकृति करे तो पायलट बोरिंग स्कीम वहां चालू करें जिस से उस इलाके की सिंचाई की गारंटी की जा सकती है। मगर वह तभी संभव होगा जब रुपया हो। अगर यह 20 करोड़ रुपया नहीं रखते हैं तो नेपाल की स्वीकृति के बाद भी कम से कम पांच साल तो उसे पूरा नहीं ही कर सकेंगे। और बाद में भी कब पूरा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि, मैं चाहता था कि प्रधान मंत्री यहां रहें, लेकिन वित्त विभाग के मंत्री मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि इस मद में जो 20 करोड़ का उनका आंका हुआ खर्चा है उसको वह प्रोवाइड करें पश्चिमी कोसी नहर के लिए और अगर वह असम्भव हो जाय तो इसके लिए एक डेलीगेशन यहां से नेपाल भेजें। फिर भी न हो तो पायलट बोरिंग स्कीम का इन्तजाम करें और यह शीघ्र से शीघ्र करें। यह मामला विलम्ब करने का नहीं है क्योंकि लोग भूखों मर रहे हैं। वहां अकाल की स्थिति अभी से हो रही है।

दूसरा मसला औद्योगीकरण का है। 22 साल की आजादी के बाद हिन्दुस्तान में केरल की जो घनी आबादी है वही उत्तरी बिहार की है तो सबसे घनी आबादी वाला इलाका, उसके औद्योगीकरण पर एक नया पैसा भी भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है। फिर भी वहां पर व्यक्तिगत रूप से और थोड़ा बिहार सरकार का हिस्सा लेकर एक बहुत बड़ा कागज का कारखाना खड़ा हुआ। एक दूसरा कारखाना भी खड़ा हुआ, अशोक पेपर मिल, इतना बड़ा कारखाना है जिसमें साढ़े सात करोड़ की पूंजी लगी है, साढे चार करोड़ की विदेशी मशीन है, साढे तीन सौ एकड़ जमीन में वह लगा हुआ है। दूसरा एक पेपर मिल समस्तीपुर का है और उसमें जो मिल बनाने वाले थे एक की मृत्यु हो गई। लेकिन

सबसे बड़ी बात कि जैन और बिरला, यह कागज के इजारेदार परिवारों ने दबाव देकर अधिकारियों के ऊपर इस मिल को चालू नहीं होने दिया। जैन और बिरला के हुक्म पर बिहार सरकार के उस समय के मंत्री चले, अभी भी उसके अफसर चलते हैं और केन्द्र पर भी असर डाला जा रहा है। अभी हमारे मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब यहां मौजूद हैं, उन्होंने 1969 की 27 मई को यह जवाब दिया है। जब हमने कहा था कि आप केन्द्र में ले लें, देश में कागज की जरूरत है। पेपर कारपोरेशन आप कायम करने जा रहे हैं और कागज की मिल वहां कायम है जिस में साढ़े चार करोड़ की विदेशी मुद्रा का सवाल है, उसमें कुछ रुपया और डालें और उसको चालू कर दें। तो उन्होंने जवाब दिया था।

> "The possibility of the Central Government taking over the mill will also be examined as soon as any Central Government scheme for the manufacture of paper is approved."

यह इनका खत है। मैं इनके खत से उध्दृत कर रहा हूं। तो यह 69 के मई में इन्होंने कहा था और फिर उसके बाद अगस्त में जो इन्होंने जवाब दिया था, उसमें भी यही कहा था।

> "As regards the Central Government taking over the mill, as I indicated in my letter of May 27, the feasibility of this will be examined as soon as any Central Government scheme for the manufacture of paper is approved.

अब चौथी पांच साला योजना में चार-पांच जगह नई कागज मिल खोलने का सवाल है और इसके लिए जहां इतनी मशीन लगी हुई है, जमीन आठ साल से बेकार पड़ी है और पूरा कारखाना तैयार है, नई रेलवे साइडिंग चली गई है, उसके लिए यह सुझाव मुझे मिला है जिसमें से थोड़ा सा अंश में उद्धृत कर दे रहा हूँ:

> "Among other terms and conditions, the main condition is that the State Government (that is the Bihar Government) are agreeable to the shifting of the required machines from Darbhanga to Assam for manufacture of 90 tons and 120 tons of paper and pulp per day respectively in Assam provided another unit of the Ashok Paper Mills Ltd. is set up at the present site at Rameshwarnagar (Darbhanga) for manufacture of 30-40 tons of high grade paper per day.

तो इस मिल की क्षमता 90 टन प्रति दिन कागज की है और 120 टन प्रति दिन पल्प की है। अब यह मशीन उठाकर ले जाएंगे आसाम और तब एक नई मशीन मंगाएंगे शायद विदेश से जो 30-40 टन सिर्फ कागज तैयार करे। . . . (**व्यवधान**) . . . अब अगर यह कहवें कि बिहार देश से बाहर है, उत्तरी बिहार देश से बाहर है, इसलिए वहां से उद्योग उठाकर लेजाएंगे तो इन की मर्जी लेकिन यह मैं कह दूं कि आखिर वहां जीव रहते हैं जिन्दा, वह उठ कर मशीन जाने नहीं देंगे, चाहे यह मशीनगन चलाएं, लोगों को गोलियों से भून दें, कुछ भी करें लेकिन मैं यह बाजाब्ता कहना चाहता हूं कि एक भी बच्चा वहां जब तक जिन्दा रहेगा मशीन वहां से उठ कर नहीं जाने पाएगी और उस को चालू करने के लिए भारत सरकार को तैयार रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस में फखरुद्दीन साहब पर इल्जाम आता है, लोगों का यह कहना है चूंकि वह आसाम के हैं, इस लिये उस को घसीट कर आसाम ले जाना चाहते हैं। यह इल्जाम मैं नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन जो खत मुझे मिले हैं उन से ऐसा महसूस होता है। मुझे आसाम में कारखाने खोलने से कोई इतराज नहीं है, दो के बजाय चार खोलिये, लेकिन हमारे कारखाने को आप वहां उठा कर नहीं ले जा सकते।

एक बार मुझे अहमद साहब ने कहा कि वहां कच्चा माल नहीं मिलेगा। मैं उन से कह देना चाहता हूं कि उस मिल के इर्द-गिर्द के इलाके में 25 चीनी मिलें हैं और ये मिलें आजादी के बाद की नहीं हैं, जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में बागास निकलता है जिससे कागज तैयार हो सकता है। इसके

[श्री भोगेन्द्र झा]

अलावा बिहार में जंगली इलाका है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में बांस के जंगल है, जिनको बिहार सरकार ने डालमिया जैन को ठेके पर दिया हुआ है। यह ठेका बहुत सस्ते दर पर दिया हुआ है और हम को डालमिया जैन के पैसे पर पले हुए अफसरान कहते है कि यह घाटे में चलेगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, कच्चे माल की वहां पर कोई कमी नहीं है। इन 25 मिलों का वगास, बिहार सरकार का बांस का जंगल उस मिल के चलाने के लिये पर्याप्त है। जब कि उस में साढ़े चार करोड़ रुपया आइ. एफ. सी. का फंसा हुआ है, 70 लाख रुपया बिहार सरकार का फंसा हुआ है, ये लोग उस को नीलाम करने या उस को उठा कर आसाम ले जाने की बात कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार इस को अपने हाथ में ले और उस को चालू कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा सवाल दरभंगा के विश्वविद्यालय को लेकर है। यह 20-22 साल पुराना सवाल है। मैं इस के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूनीवर्सिटी ग्रान्टस् कमीशन ने अपनी एक टीम, वहां पर भेजी थी, उन्होंने सुझाव दिया कि इसको पुनर्गठित कर के मिथिला विश्वविद्यालय बनाया जाय। इस विश्वविद्यालय के लिये 2 करोड़ रुपये का मकान और पुस्तकालय मिल रहा है। मैं समझता हूं कि देश में किसी भी विश्वविद्यालय के लिये अभी इतना संभव नहीं हो सका है, लेकिन इस सरकार की तरफ से इस में विलम्ब किया जा रहा है। यह तो पहले ही सरकार का होना चाहिये था, क्योंकि वह दरभंगा राज्य का मुख्यालय था, लेकिन अब वे उस को दे रहे हैं। मैंने इस के संबंध में राव साहब को पत्र लिखा था कि आप इस को स्वीकार कर लें और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इस को चलायें। चूंकि दरभंगा प्राचीन संस्कृत का विख्यात शिक्षा केन्द्र रहा है, जहां के लोग भूखे रह कर भी पढ़ना पसन्द करते हैं, शिक्षा हासिल करना पसन्द करते हैं और करते आये हैं, इसलिये यह मामला टलना नहीं चाहिये, कमीशन की सिफारिश को मान कर इस को फौरन लेने की व्यवस्था की जाय।

लेकिन इसके संबंध में हाल में मुझे जो पत्र मिला है, वह बड़ा ही भयानक है। यह पत्र मुझे पार्लियामेन्ट्री विभाग की मिनिस्ट्री से मिला है, जिसमें कहा गया है—

> "The report of the UGC Committee was referred to the State Government of Bihar. The State Government enquired as to what amount of assistance the Government of India, i.e. UGC make available towards the establishment of the university. The University Grants Commission indicated the amount of assistance tha. it could offer to the State Government. It had yet to consider the report of this committee after the receipt of the State Government's comments thereon. Nor have this Ministry any scheme under which assistance could be given to the State Government for this purpose. This position was explained to the State Government."

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यू. जी. सी. की सिफारिश है कि यह होना चाहिये : बिहार की सरकार भी इस को करना चाहती है और उसने पूछा है कि आप बताइये, इस में क्या मदद देंगे, लेकिन ये कहते हैं कि हम बताने की स्थिति में नहीं हैं। इस तरह से यह मामला लटाका हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मदद से यह काम हो सकता है।

आखिरी बात, मुझे प्रसारण केन्द्र के संबंध में कहनी है। जब श्री के. के. शाह इस मंत्रालय के मंत्री थे, उनके एक खत का उद्धरण मैं यहां देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था—

> "I have looked into the matter and find there is a proposal to set up a radio station in Darbhanga under the Fourth Plan. We propose to take action on this project next year as soon as the necessary funds are made available to us. However, this could be discussed in a meeting that I propose to hold. Regarding your suggestion for the introduction of Programmes in Maithili, the question could be considered when the Darbhanga station goes on the air."

यह खत 3 नवम्बर, 1967 का है। आखरी खत जो मुझे मिला उसमें कहा गया है—

"I need hardly assure you of my own anxiety to provide a transmitted for Darbhanga station. I hope to secure early approval of the oroject so that it could make a start in the year 1969-70."

इस खत के अनुसार यह काम 1969-70 में हो जाना चाहिये था। उस के बाद श्री सत्यनारायण सिंह मिनिस्टर हुए, जो लोगों से वोट के लिये एक वायदा करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। अभी जो बजट पेश हुआ है जिसमें देश में 5 नये प्रसारण केन्द्रों के लिये व्यवस्था की गई है, लेकिन उन में दरभंगा का नाम नहीं है। मैं चाहता हूं कि उपर्युक्त आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए सरकार एलान करें कि यह भी इसी साल में शामिल कर लिया जायगा।

इस के संबंध में एक और पहलू भी आपके सामने रखना चाहता हुं—आधा नेपाल का जो हिस्सा है, तराई का क्षेत्र, जिसमें जनकपुर आता है, यह सब मैथिली भाषा-भाषी क्षेत्र है। नेपाल के साथ हमारे सहोदर के संबंध हैं और हम उस संबंध को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। उस इलाके के लोगों के साथ हमारे नाते-रिश्ते और दोस्तों के सम्बन्ध हैं। कई हजार नेपाल के छात्र वहां के स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं। इस प्रसारण केन्द्र के खुल जाने से दो सहोदर देशों में दोस्ती का गाढ़ा रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों सवालों पर सरकार फौरन कदम उठाये। मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना के रास्ते पर हमारे लोगों को भी जाना पड़े और फिर आपको यहां से मिशन कमीशन भेजना पड़े।

SEVERAL HON. MEMBERS—*rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are only 10 minutes. Kindly co-operate.

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : हम दो मिनट चाहते हैं, हम को सुन लीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। यह 193 के अंतर्गत डिस्कशन है, कभी भी आधा घन्टे में खत्म नहीं होता है।

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Please allow two minutes at least to my party also. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: First take your seats. Let me understand what you say. If you all want to speak, it is impossible, unless you decide that we sit longer.

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मिथिला का इलाका बार्डर से सटा हुआ है। आप जानते हैं......

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me have the sense of the House. The main thing is, you have agreed to half-an-hour.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : We have not agreed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is for the House to decide whether you are going to sit after 7 p. m.

SOME HON. MEMBERS : No.

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की खबर दे रहा हूं। आज दरभंगा में एक लाख लोगों ने बिहार के भूतपूर्व उपमुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है और उन्हें इन्हीं मांगों को लेकर किया है। मुझे इस बात का डर है—चूंकि मैं उस क्षेत्र का पड़ौसी हूं—वहां जिस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है, आपके मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र यहां बैठे हैं, इन्होंने भी कहा था कि मिथिला सेना का संगठन किया जायगा। चूंकि दरभंगा हिन्दुस्थान का सब से पापुलेटेड इलाका है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me as certain the wishes of the House. If you do not stop, I will not have anything recorded. It is now eight minutes to 7 p.m. You please decide up to what time you are going to sit in order to finish this discussion. I cannot proceed in this way; the House must decide.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा प्रस्ताव है कि डिस्कशन का टाइम बढ़ा दिया जाय, कम से कम एक घन्टा बढ़ाया जाय.... (**व्यवधान**) .....

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. It is impossible. Do not take down anything.

SHRI GUNANAND THAKUR: *

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want this to be settled first. Up to what time you want the House to sit for finishing this discussion?

श्री रामावतार शास्त्री : आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a proposal from Mr. Shastri that the sitting of the House should be extended by half an hour.

The question is:

"That the sitting of the House be extended by half an hour in order to finish this discussion."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House has rejected the proposal. *(Interruptions).* Nothing will go on the record now. *(Interruptions).**

श्री रामावतार शास्त्री : 15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is another proposal now that we extend the sitting by 15 minutes. Does the House agree with it?

HON. MEMBERS : Yes.

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, वहां की स्थिति की क्या भयंकरता है उसके संबंध में मैं इस सदन का और खासकर मंत्रियों का ध्यान खींचना चाहता हूं । कांग्रेस के श्री गणेश चन्द्र मिश्र ने एक पर्चा केन्द्रीय सरकार को दिया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तीन महीने के अन्दर इन कार्यों की पूर्ति नहीं हुई तो उस इलाके में भारी विद्रोह होगा । मैं ने पहले कहा कि आज दरभंगा में एक लाख लोगों का प्रदर्शन श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हुआ । इस मामले में सभी एक राय के हैं । इसलिए सरकार ने बड़ी भूल की और बड़ी गैर जिम्मेवारी से काम किया कि पश्चिम कोसी नहर के सवाल पर जब चुनाव का मौका आया तो जिम्मेदार लोग और मंत्रियों ने जाकर उद्घाटन किया कभी श्री विनोदानन्द झा ने मुख्य मंत्री की हैसियत से और कभी बाबू जगजीवन राम ने केन्द्रीय मंत्री की हैसियत से जाकर उद्घाटन किया । मैं डा. के. एल. राव से खासकर जानना चाहता हूं कि यदि नेपाल सरकार से आपका एग्रीमेन्ट नहीं हुआ तो किस आधार पर मंत्रियों ने जाकर उद्घाटन किया और टेंडर मांगे गए और यह कहा गया कि इसको चालू किया जायेगा ।

जहां तक मिथिला विश्वविद्यालय का सवाल है, मुझे याद है कि मैं शिक्षा मंत्री श्री वी. के. आर. वी. राव से श्री कर्पूरी ठाकुर के साथ मिला था । बिहार कैबिनेट ने तय करके शिक्षा मंत्री और केन्द्रीय सरकार को लिखा था लेकिन पता नहीं वह फाइल कहां है । जब भी हम सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि विचार हो रहा है ।

श्री भोगेन्द्र झा ने जो तीसरा सवाल उठाया है कि दरभंगा, उत्तर बिहार में एक उद्योग है अशोक पेपर मिल, करोड़ों रुपए का जिसको बर्बाद करने की बात की जा रही है । इससे वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है । इसलिए मैं अपनी पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो कि दरभंगा जिले में सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री लोग जनता में जाकर दूसरे भाषण करते हैं लेकिन यहां पर आकर बदल जाते हैं, यह बात अब नहीं चलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा, सहर्सा और पूर्णिया का लिंक कटअप है । डा. के. एल. राव खुद मेरे साथ गए थे उस इलाके में । सहर्सा और दरभंगा को मिलाने के लिए बरसों से मांग चल रही है लेकिन उस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा

* Not recorded.

रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटिजिक प्वाइन्ट आफ व्यू से आज जिस तरह से नेपाल और हिन्दुस्तान का रिश्ता बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन और जो हालत हो गई है, हम लोग जो सरहदी इलाके के एम. पीज हैं जिनका एरिया बार्डर सर सटा हुआ है, अगर आप से पश्चिम नहर का सवाल हल नहीं होता है तो बार्डर एरिया के एम. पी. होने के नाते हमको कांठमांडू भेंजे ताकि वहां के राजा और वहां की जनता की भावना हम ठीक कर सकें।

मैं सरकार से हाथ जोड़ कर आग्रह करना चाहता हूं कि अविलम्ब इन समस्याओं पर ध्यान दें नहीं तो वह इलाका एक दूसरा तेलंगाना हो जायगा और वहां की हालत अगर बदतर हो गई तो उसकी सारी जिम्मेवारी इस सरकार पर होगी।

(19.00 hrs.)

श्री क. मि. मधुकर (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है, दरभंगा में खासकर कोसी नहर के सवाल को लेकर इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है कि चार चार एम. एल. ए. और मुखिया जेलों में हैं। इसके साथ साथ मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डा. के. एल. राव ने बार बार आश्वासन दिया है कि गंडक नहर को जल्दी से जल्दी तय करने के लिए ध्यान दिया जायेगा लेकिन आज स्थिति यह है कि यू. पी. में और छपरा जिले में गंडक नहर की योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। सारी जमीन ले ली है। किसानों से जमीन लेने के बावजूद उनसे मालगुजारी वसूल की जाती है और गंडक नहर का काम नहीं हो रहा है। मैं ने बार बार कहा है कि उस योजना को केन्द्रीय सरकार की योजना के रूप में लिया जाये लेकिन वह नहीं ली जाती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गंडक नहर के लिए अनुदान दिया जाये और उसका छपरा जिला और यू. पी. में शुरू हो।

इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि श्री के. के. शाह ने पांच पत्र लिखे कि चम्पारन में एक रेडियो स्टेशन खोला जायेगा लेकिन उन 5 पत्रों के बावजूद समझ में नहीं आता कि वे क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते हैं। लिखने के बाद भी उस बात को पूरा नहीं करते हैं। अगर उसको पूरा नहीं करना था तो फिर पत्रों को लिखने की क्या जरूरत थी? इसलिए मैं चाहूंगा कि इंफार्मेशन मिनिस्टर साफ साफ कहें कि चम्पारन में रेडियो स्टेशन खोलने का जो उनका आश्वासन था उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। कोसी नहर को पूरा करने के सिलसिले में, गंडक नहर को पूरा करने के सिलसिले में और चम्पारन में रेडियो स्टेशन खोलने के लिए यहां पर निश्चित आश्वासन दिये जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मांगें उठाई गई हैं उनका मैं पूरा पूरा समर्थन करता ही हूं लेकिन इन्हीं मांगों के सम्बन्ध में सरकार की अब तक जो नीति रही है। उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। एक जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बल्लभ सहाय जो कि सिन्डीकेट के लीडर हैं उन्होंने एलान किया था बिहार को औद्योगिक मान चित्र पर लाकर खड़ा करेंगे। वे तो चले गए लेकिन औद्योगिक मानचित्र में बिहार को आगे नहीं बढ़ा सके बल्कि उलटा यह हो रहा है कि पेपर मिल को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ही हमारे पटना में जो साइकिल का कारखाना था जहां पर बहुत अच्छी साइकिलें बनती थीं उसको चौपट कर दिया। इसके अतिरिक्त इस सदन में मन्त्री महोदय से कई दफे प्रश्न हुए लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया हम कर नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना है कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ है यह आप जानते हैं। वहां पर और ज्यादा उद्योग-धंधे बिठाने की आवश्यकता है, खास तौर पर उत्तर बिहार में लेकिन आप उसको न करके पेपर मिल को कहीं हटा दे रहे हैं, कहीं साइकिल फैक्टरी को बन्द कर रहे हैं। आपकी यह नीति बिहार की जनता के लिए जनता विरोधी नीति है। इसका परिमार्जन होना चाहिए। मन्त्री महोदय को किसी भी कीमत पर उस पेपर मिल को वहां से हटाना नहीं चाहिए।

आखिरी बात यह है कि जब मन्त्री लोग कोई आश्वासन देते हैं तो उसके लिए कोई कायदा भी होना चाहिए। हम लोग क्या समझें कि ये लोग मुंह से बात बोलते हैं या क्या करते हैं मालूम

[श्री रामावतार शास्त्री]

नहीं । जब ये आश्वासन देते हैं तो उन आश्वासनों को पूरा भी करना चाहिए । अगर उनको पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आश्वासन भी नहीं देने चाहिए नहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर के इनके खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि ये आश्वासन तोड़ने वाले मिनिस्टर हो गए हैं । इन शब्दों के साथ जो भी चार मांगें यहां पर उठाई गई है उनका मैं पूरा पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री बेनीशंकर शर्मा (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भोगेन्द्र झा ने दरभंगा के सम्बन्ध में जो मांगें उपस्थित की है मैं उनका समर्थन करते हुए केवल अशोक पेपर मिल के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं । मैं अशोक पेपर मिल का एक शेअर-होल्डर भी हूं और उसके जो प्रमोटर थे उनसे सम्बन्धित भी हूं । इसलिये मैं जानता हूं कि किस परिस्थिति में अशोक पेपर मिल शुरु की गई थी । दरभंगा के आसपास बहुत सी शुगर फैक्ट्रियां हैं और उनमें बगास होती है । अशोक पेपर मिल में जो मशीनरी लाई गई है वह विशेषकर बगास से कागज बनाने में काम आ सकती है । मेरी समझ में नहीं आता कि अब इस मशीनरी को उठाकर असम ले जाने में क्या तुक है । अगर वहां लकड़ी बहुत है तो बिहार में भी बांस और लकड़ी की कमी नहीं है । वहा और भी नई पेपर मिले बढ़ाई जा सकती हैं । अगर कोई पोलिटिकल रीजन हो तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं । मैं और मेरी पार्टी असम, बंगाल और बिहार में कोई फर्क नहीं मानते । लेकिन जो बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उसमें दरभंगा जिला तो एक सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । जैसा आपने अभी सुना वहां सबसे अधिक गरीबी है, वहां जमीन की कमी है और कोई उद्योग भी नहीं है । सिर्फ एक अशोक पेपर मिल शुरु की गई थी । और वह भी बंद की जा रही है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर असम में आवश्यकता है तो कोई दूसरी मिल वहां स्थापित करें इस मिल को उठाकर वहां ले जाना एक नेशनल वेस्ट होगा ।

डॉ. के. एल. राव से नहरों के सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि वे डैम बनाते हैं, नहरे बना रहे हैं । लेकिन कम से कम अपने इंजीनिअरों से कहें कि वे थोड़े दिमाग और बुद्धि से भी काम लें । जो कोसी नहर बनी है उस के बारे में एक छोटा सा समाचार है दो लाइन का, जो 4 तारीख के "आर्यावत" में निकला है जो सहरसा का है :

"कोसी नहर में पानी की व्यवस्थिति सुविधा न होने के कारण सहरसा गांव और दूसरे छोटे गांवों की लगभग 10,000 एकड़ भूमि बेकार हो गई है ।"

कोसी की जो नहरें बनी हैं उन के जरिये खेतों में इतनी बालू आ जाती है कि पूर्णिया के अधिकांश क्षेत्र में जो हरी क्रान्ति होनी थी वह पीली क्रान्ति में परिवर्तित हो गयी है और वहां की पैदावार बढ़ने के बदले कम हो गई है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब भी कोई नहरें बनें तब उनके पानी के साथ खेतों में बालू न जाय कम से कम वह इस की कोई व्यवस्था करें ।

श्री शिव नारायण : कोसी नहर इंटरनेशनल क्वेश्चन है । यह इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का सवाल है और बड़ा जेनुइन प्रश्न है । मैं इन सब बातों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह गवर्नमेंन्ट भी इस को मान कर कोसी नहर के प्रबन्ध को ठीक करेगी ।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : क्या यह सत्य है कि मैथिलि भाषी जनता की घोर उपेक्षा के खिलाफ अपनी भावना को प्रकट करते हुए किसी केन्द्रीय राज्य मंत्री ने यहां तक कहा कि यदि यह उपेक्षा मैथिलि भाषी जनता की जारी रही तो कहीं अलग मैथिलि राज्य न बन जाय ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I quite appreciate the hon. Member's anxiety on the question of the Western Kosi Canal. This Canal has had a very long history. Though sanctioned in 1961

by the Planning Commission, it took five years to enter into an agreement with the Government of Nepal. After that joint surveys were done for two years by the engineers of India and Nepal. Everything had been finalised. After that the Nepalese Government wanted some things to be done. They wanted some irrigation canals and the percentage of rice to be increased. All that has been agreed to and now there is no other demand from the Government of Nepal. Therefore we are expecting naturally the sanction of this project at any time.

I quite agree with the hon. Member, Shri Jha, that we should take every step to expedite the Project. He made some suggestion of sending a delegation and so on. I do not know how far it is practicable. But I will pass on the information to the Ministry of External affairs to see what can be done.

I entirely agree that the Western Kosi Canal had a chequered career and it is necessary that we should request the Nepalese Government to see that that project is approved by them. They are concerned only with the first 22 miles of the Canal and they should accept the alignment for that portion.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): Mr. Deputy-Speaker, Sir, so far as the question regarding Ashok Mill is concerned, I would like to place certain facts before the House so that it may realise the actual situation and circumstances why this Mill has not Started functioning there. The licence was given for starting this Mill in 1956 and three years later an import licence for importing machinery worth Rs. 238 lakhs from France was issued. This amount was was to be paid on deferred payment system and the Government and the bank had to stand guarantee for this payment. A loan of about Rs. 1 crore was taken from the I.F.C. and equity shares were also raised from the L.I.C. and others.

The plant was to go into production in 1965. But till now except the completion of civil works, nothing has been done. The machinery is there. It is in that stage that they were ngotiating first with the private and then they approached the Central Government as to whether it will be possible for the Government to take over the plant. We had the matter examined by the National Industrial Development Corporation. They submitted a feasibility report on the basis of which the Government found that it would be a financial loss. There was no raw material available and, therefore, the Central Government. . . (*Interruption*)

SHRI BHOGENDRA JHA: The officers reported on the orders of Birla and Jain. . . (*Interruptions*)

श्री गुणानन्द ठाकुर : मंत्री महोदय, सिर्फ इतना आश्वासन दें कि वह कोई उच्च-स्तरीय जांच कमेटी बिठलायेंगे । अगर वह एक्स्पर्ट कमेटी कह दे कि रा मैटीरियल मिलने वाला नहीं है, तो हम उसके बाद कुछ नहीं कहेंगे । (व्यवधान)

SHRI F. A. AHMED: I am not prepared to yield.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Whatever reply he has given is there. You can pursue other avenues that are left to you.

SHRI F. A. AHMED: May I submit it is no use shouting? The matter was referred by the State Government to the N.I.D.C. for submission of a feasibility and rehabilitation report. On considering that report, the Government of India decided that it would not be possible for them to participate in a very losing concern.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Will you accept Bihar Government's recommendation now?

SHRI F. A. AHMED: The Bihar Government is entitled to run it if they want.

SHRI YOGENDRA SHARMA: They have no money. If the Bihar Government says that this factory can be set up, will you accept that and run it ?

SHRI F. A. AHMED: Why don't they do it?

SHRI BHOGENDRA JHA: They need finance from you.

SHRI F. A. AHMED: There is nothing to prevent to Bihar Government from running the paper mill.

Then, another allegation has been made that because I come from Assam, I am interested in the transfer of this plant from Bihar to Assam. May I say that so far as I am concerned, I am personally opposed to the transfer of this plant from Bihar to Assam. It is as a result of negotiation between the Assam Government and the Bihar Government that they have decided to have part of the plantin Assam and the other part in Bihar for which they are also submitting proposals.

SHRI BHOGENDRA JHA: You do not know the facts. New machinery will be imported afterwards. The entire existing machinery will be shifted to Assam.

SHRI F. A. AHMED: I can tell him that the matter has been sent to me. But we are actually starting a paper mill in the public sector in Assam and we have nothing to do with the Ashok Mill. I do not know the negotiation between the Assam Government and the Bihar Government on the basis of which a petition had been filed before the High Court and the Liquidator and certain orders have been obtained. That is the only information I have. So far as we are concerned, we have not taken any such action.

SHRI BHOGENDRA JHA: When you are setting up a new paper mill in Assam, why can't the Centre take this over on the basis of the assurance that I read out from your letter. I read out that part of the letter. Why don't you consider and take it over?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Let the plant go to Haryana.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not know why I should have been brought into this discussion, a very interesting discussion. As far as establishment of Sanskrit University is concerned, Mr. Deputy-Speaker, Sir, several times I have answered questions on this subject. (*Interruptions*) I am sorry I cannot help. The University Grants Commission's report still remains without any comments from the Bihar Government. There is another organization called Bihar State University Commission. They do not like the idea of the amalgamation of the Sanskrit University with the proposed multi-faculty Mithila University. We have not received any reply from the State Government giving their comments on the subject. We had been writing to them and I have also talked to a number of Members privately. We have been sending letters but we get no reply. At one time, they were afraid that the executor of the Dharbanga State may sell away those buildings. So I went out of my way and took action. The matter is under consideration with the University Grants Commission and we are waiting for the State to take action on that particular matter.

Regarding the question whether the Central Government is in a position to give financial assistance, I deeply regret, Sir, that the demands for Central Universities are coming from all over the country. (*Interruptions*) I wish my hon. friend moved a private Members' Resolution that the Government of India should have 20 or 30 such universities. Let them suggest wherefrom this could be done by cut from the existing budget. As far as I am concerned, I would like to have as much money as possible for education. But I cannot create money.

The Central Government is not in a position to find money for setting up Central Universities. The University Grants Commission can help a new University after it is established. They can help for developmental purposes. Once the Bihar Government establishes the University, then for developmental purposes the University Grants Commission can help them. It is entirely within their terms of reference. I don't think therew ill be any difficulty, but the initiative rests with the State.

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : श्री भोगेन्द्र झा ने दरभंगा में रेडियो स्टेशन बनाने की बात कही है। 22 नवम्बर 1967 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें बिहार के पार्लिमेंट के मैम्बर उपस्थित थे। उसमें यह निर्णय किया गया कि भोजपुरी और मैथिलि बोलने वाली जो आबादी है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की उनके लिए गोरखपुर में रेडियो स्टेशन बनाया जाए और दरभंगा में मैथिलि के लिए बनाया जाए।

गोरखपुर स्टेशन के मामले में तो काफी काम आगे बढ़ चुका है जैसाकि 4 दिसम्बर 1969 को हाउस में जवाब दिया गया था। दरभंगा में भी चौथी योजना में रेडियो स्टेशन बन जाएगा। उसका काम कुछ शुरू हो चुका है। ट्रांसमिटर के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए कलेक्टर को 23 फरवरी 1970 को कह दिया गया है और उसके लिए जो खर्चा है वह भी मंजूर कर दिया गया है 23 फरवरी 1970 को ही। इसी तरह से स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर्ज के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि वह जमीन एक्वायर करके दे दें। इक्विपमेंट के लिए आर्डर प्लेस कर दिये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दरभंगा में रेडियो स्टेशन जल्दी से जल्दी से बन जाए। अंतरिम रिकार्डिंग स्टूडियो दरभंगा में बना दिया गया है पिछले साल से। वहां पर रिकार्डिंग कर लेते हैं मैथिलि भाषा में और पटना से उसका ब्राडकास्ट कर देते हैं। जब तक वह नहीं बनता है तब तक रिकार्डिंग का प्रबन्ध कर दिया है।

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

MINUTES

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar): Sir, I beg to lay on the Table the Minutes of the 1st to 20th sittings of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 1st to 8th sittings of the Sub-Committee thereof.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

19.20 hrs.

The Lok Subha then adjourned till Eleven of th· Clock on Wednesday March 11, 1970/Phalguna 20, 1891 (Saka).

NAI DUNIA PRESS, INDORE. 1010 —6-1970